वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) अवधाकों को उच्च-स्तरों पर पदोन्नत करने के लिए आरक्षण आदेश तथा 40-सूत्री रोस्टर एम एम टी सी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

Export/Import plans submitted by large industrial houses

2731. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have asked large industrial houses to present their export and import plans for the current year to boost exports;

(b) if so, the details of the large industrial houses which have submitted their export and import plans to Government;

(c) whether Government have since examined these plans; and

(d) if so, the details of the changes likely to be made on the basis of these plans in the Import/Export policy to boost exports?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) Yes, Sir.

(b) List of the 18 Large Industrial Houses with whom meetings have been held so far is given in the attached statement. (See below)

(c) and (d) The export projections for coming years have been discussed with these Large Industrial Houses. No specific change is likely to be made in the Export-Import Policy on the basis of the projections made by these Large Industrial Houses.

Statement

1. Larsen & Toubro
2. I.C.I. Group
3. Thapars Group
4. Ranbaxy Group
5. Bajaj Auto
6. Britannia
7. Mahindra and Mahindra Group
8. Arvind Mafatlal Group
9. Mukand Group
10. Ashok Leyland
11. M.R.F. Group
12. H. S. Singhania Group
13. Kirloskar Group
14. I.T.C. Group
15. Usha Martin Group
16. Arvind Lalbhai Group
17. V. K. Modi Group
18. Hindustan Lever Group

मसाला बोर्ड के लिए निर्धारित परिव्यय

2732. श्री अजीत जोगी :
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान काली मिर्च की खेती की सुरक्षा प्रदान करने तथा उसके विकास हेतु मसाला बोर्ड के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या स्वीकृति धनराशि मसाला बोर्ड के कार्यकलापों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और काली मिर्च के निर्यात से होने वाली आय के समानुपात में है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) काली मिर्च के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और कृषि मंत्रालय की है। तथापि, मसाला बोर्ड ने केरल के कुछ जिलों में किसानों को क्वालिटी काली मिर्च की कलमें और पादप-संरक्षण उपस्कर सप्लाई करके उत्पादन के लिए अभिज्ञात कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में 23.60 लाख रुपए खर्च किए हैं;